1998-99 में जारी रखा जा रहा है। इस स्कीम के तहत, क्वालिटी की पौध सामग्री के वितरण हेतु नर्सरियों एवं टिश्यू कल्चर यूनिटों की स्थापना, क्षेत्र विस्तार, जीर्ण बागानों के नवीकरण, किसानों के प्रशिक्षण एवं प्रसार उपाय करने हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।

डी०एम०एस० को घाटा

1735. **श्री बलवन्त सिंह रापूवालियां:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना (डी०एम०एस०) को पिछले कुछ वर्षों से लगातार घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1998 तक डी०एम०एस० को कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ग) इस योजना के संचालन के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से मार्च, 1998 तक डी०एम०एस० में कुल कितना पूंजी-निवेश किया गया था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली दुग्ध योजना को मार्च, 1998 तक कुल 401.94 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यह राशि मार्च, 1992 तक के लेखा परीक्षित प्रोफार्मा लेखों पर आधारित है और उसके बाद अनन्तिम लेखों पर आधारित है। दिल्ली दुग्ध योजना को कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की अनुदान मांगों के हिसाब से सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष योजना और गैर-योजना खर्च के लिए निधि आवंटित की जाती है। इसमें अन्य किसी स्रोत के जरिए पूंजी निवेश का कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अर्जित धनराशि को भारत की संचयी निधि में जमा कर दिया जाता है। व्यय और प्राप्त राजस्व के बीच जो अंतर होता है उसे सरकार द्वारा बजटीय समर्थन के रूप में प्रदान किया जाता है।

प्याज का भंडारण

1736. **श्री रमा शंकर कौशिक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 के दौरान प्याज का कुल कितना उत्पादन हुआ था;

(ख) सरकार द्वारा घरेलू खपत के लिए प्याज की कितनी मात्रा का भंडारण किया गया है;

(ग) क्या सरकार प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) 1998-99 के दौरान प्याज का उत्पादन 4.72 मिलियन टन तक होने का अनुमान है।

(ख) भारत सरकार की प्याज के भण्डारण की कोई स्कीम नहीं है।

(ग) और (घ) पहली फरवरी, 1999 को प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा लिया गया और बंगलौर रोज प्याज तथा कृष्णापुरम प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई। सरकार से सरकार को माल भेजने के आधार पर श्रीलंका को 3,000 मीटरी टन प्याज का निर्यात करने की दोनों सरकारों की पारस्परिक अनुमति भी प्रदान की गई। 12 फरवरी, 1999 को सम्पर्क एजेंसियों के जरिये अगले तीन महीनों के लिए 25,000 मीटरी टन प्याज प्रति माह निर्यात करने की अनुमति भी अधिसूचित की गई।

Special scheme to modernise agriculture

1737. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of special scheme to modernise agriculture in all the States and Gujarat in particular in order to make them self sufficient in production of foodgrains;

(b) the steps taken to provide high yielding variety of seeds and fertilizers in time and at cheaper rates;

(c) whether consumption and availability of fertilizers in Gujarat is less than other States; and

(d) if so, the remedial measure taken by Government in this regards?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) A number of Central/Centrally Sponsored Schemes are being implemented by Union Government for the development of agriculture, as also to supplement the efforts of the State Governments for increasing the productivity and production of food-